Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2022

सरकारी नीतियाँ और पहल

(जनवरी 2021 – मार्च 2022)

Answers Answers Answers Answers Explanation Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers

Detailed Explanation

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtiias.com

Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

उत्तर

1.

उत्तर: B

व्याख्या:

अमृत मिशन (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)

- इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था
- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मिशन है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- उद्देश्य:
  - यह सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल है। अत: कथन 2 सही है।
  - मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र जल आपूर्ति और उसके बाद सीवरेज है।
  - हरियाली और अच्छी तरह से खुले स्थान (जैसे पार्क) विकसित करके शहरों की सुविधाओं में वृद्धि करना।
  - सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।

2.

उत्तर: B

व्याख्या:

- वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
  - यह मिशन 'जल शक्ति मंत्रालय' के अंतर्गत आता है।
- यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
  - यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
- विशेषताएँ:
  - जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।
  - वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  - यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- फंडिंग पैटर्न:
  - केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है। अत: कथन 2 सही है।

3.

उत्तर: C

व्याख्या:

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा (NASP) जारी किया है, जिसके तहत संबंधित सेवाओं और उनके उपकरणों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी और ऐसा नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
- नीति में देश में हवाई खेलों के लिये दो स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 'एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (ASFI) नामक एक शीर्ष शासी निकाय और प्रत्येक हवाई खेल के लिये विशिष्ट संघ शामिल होंगे। अत: कथन 1 सही है।
  - 'एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा और लॉज़ेन स्थित (स्विट्ज़रलैंड) 'फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल (FAI) तथा हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अत: कथन 2 सही है।
    - यह हवाई खेलों के विभिन्न पहलुओं का विनियमन करेगा, जिसमें प्रमाणन, प्रतियोगिताएँ आयोजित करना, पुरस्कार और दंड आदि शामिल हैं।
  - प्रत्येक हवाई खेल संघ उपकरण, बुनियादी अवसंरचना, कर्मियों और प्रशिक्षण हेतु अपने सुरक्षा मानकों का निर्धारण करेगा तथा गैर-अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट करेगा। ऐसा करने में असमर्थ होने पर ASFI द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  - यह प्रस्तावित है कि देश में लोकप्रिय हवाई खेल क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग, सिक्किम में गंगटोक, महाराष्ट्र में हडपसर और केरल में वागामोन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हवाई खेलों के लिये एक 'नियंत्रण क्षेत्र' घोषित किया जा सकता है।

4.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा 'PM फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना के अंतर्गत छह, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड लॉन्च किये गए हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिये NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें से छह ब्रांड अमृत फाल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स की सभी व्हीट कुकीज़ हैं।
- यह 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में, विधायिका युक्त केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। अत: कथन 1 सही है।

5.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) कार्यक्रम के तहत LED लाइटों के वितरण और बिक्री के सात वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किये हैं।
- देश भर में वितरित 36.78 करोड़ से अधिक LEDs के साथ यह पहल दुनिया के सबसे बड़े ज़ीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई है। अत: कथन 1 सही है।
- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया और इसे एलईडी-आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (DELP) के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य सभी के लिये ऊर्जा के कुशल उपयोग (अर्थात् इसकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था) को बढ़ावा देना है।
- ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) को इस कार्यक्रम के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- प्रत्येक परिवार जो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिये पात्र है।

6.

उत्तर: B

व्याख्या:

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- PRASHAD योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए तीर्थ यात्रा पर्यटन का उपयोग करना।
  - तीर्थ स्थलों के विकास में गरीब समर्थक पर्यटन अवधारणा और समुदाय आधारित विकास का पालन करना।
  - सार्वजनिक विशेषज्ञता और पूँजी का लाभ उठाना।
  - धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढ़ाना।
  - बेहतर जीवन स्तर, आय के स्रोतों में वृद्धि और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में उनके लिये पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - पहचान किये गए स्थानों में आजीविका उत्पन्न करने के लिये स्थानीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना। अत: कथन 2 सही है।

7.

उत्तर: B

व्याख्या

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास को 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु NBHM के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समग्र समग्र विकास और संवर्द्धन के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी होगी। अत: कथन 2 सही है।
- हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है।
  - मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण हेतु दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी।

8.

उत्तर: C

व्याख्या:

प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकारी पहलें

- प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY): प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना।
- प्रवासी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम (SPDC): स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) और अनिवासी भारतीय (NRI) छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- 'भारत को जानो' कार्यक्रम (केआईपी): यह भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराता है।
- ई-माइग्रेट सिस्टम: यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। यह कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है।
- VAJRA (उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा) योजना: यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर एक संक्षिप्त अवधि के लिये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा करते हैं, अपनी विशेषज्ञता की सेवा देते हैं
- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव): यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की परियोजना है जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। अत: विकल्प C सही है।

9.

उत्तर: B

व्याख्या:

- इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाज़ार पहुँच तथा वैश्विक बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है। अत:कथन 1 सही है।
- कृषि पर समझौते के तीन स्तंभ:
  - घरेलू समर्थन: यह घरेलू सब्सिडी में कमी का आह्वान करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है।
    - इस प्रावधान के तहत विकसित देशों द्वारा सहायता के कुल मापन को 6 वर्षों की अवधि में 20% और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 13% कम किया जाना है।
    - इसके तहत सब्सिडी को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है:
- ग्रीन बॉक्स:
  - इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यत: व्यापार में या तो विकृति उत्पन्न करती नहीं है या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है।
  - इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इसलिये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध नहीं होता है, बशर्ते यह नीति-विशिष्ट मानदंडों के अनुरूप हो।
- अंबर बॉक्स:
  - इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियाँ आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं।
  - इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। अत: कथन 3 सही है।
- ब्लू बॉक्स:
  - यह "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स"(Amber Box With Conditions) है। इसे एसी स्थितियों में कमी लेन हेतु डिज़ाइन किया गया है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न करती हैं।
  - आम तौर पर एम्बर बॉक्स में शामिल उस सब्सिडी को नीले बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राप्त करने के लिये किसानों को अपना उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
  - वर्तमान ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है।
- बाज़ार तक पहुँच: विश्व व्यापार संगठन में माल के लिये बाज़ार की पहुँच का अर्थ शर्तों, टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों से है, जो सदस्यों द्वारा अपने बाज़ारों में विशिष्ट वस्तुओं के प्रवेश पर लगाए जाते हैं।
  - बाज़ार तक पहुँच सुनिशित करने के लिये आवश्यक है कि मुक्त व्यापार की अनुमति देने के लिये अलग-अलग देशों द्वारा निर्धारित टैरिफ (जैसे कस्टम ड्यूटी) में उत्तरोत्तर कटौती की जाए। इसके लिये देशों को टैरिफरहित शर्तों को हटाकर टैरिफ ड्यूटी में में बदलने की भी आवश्यकता थी।
- निर्यात सब्सिडी: कृषि इनपुट/निवेश वस्तुओं पर सब्सिडी, निर्यात को सस्ता बनाना या निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अन्य प्रोत्साहन जैसे- आयात शुल्क में छूट आदि को निर्यात सब्सिडी के तहत शामिल किया गया है।

- इनके परिणामस्वरूप अन्य देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाले (और सस्ते) उत्पादों की डंपिंग हो सकती है जिससे उन देशों के घरेलू कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।

10.

उत्तर: C

व्याख्या

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये 'प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0' (NEAT 3.0) की घोषणा की है।
  - NEAT योजना का मॉडल: यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी (एड-टेक) कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। अत: कथन 1 सही है।
  - उद्देश्य: NEAT का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सुविधा के लिये शिक्षा अध्यापन में सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों को एक मंच पर लाना है।
  - लक्षित क्षेत्र: इसके तहत अत्यधिक रोज़गार योग्य कौशल वाले विशिष्ट क्षेत्रों में सीखने या ई-सामग्री के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - कार्य पद्धति: इसके तहत सरकार एडटेक कंपनियों द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की एक शृंखला के लिये मुफ्त कूपन वितरित करने की योजना बना रही है। अत: कथन 2 सही है।
  - कार्यान्वयन एजेंसी: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

11.

उत्तर: A

व्याख्या:

- नारी शक्ति पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया। यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अत: कथन 1 सही है।
  - प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और व्यक्तियों एवं संस्थानों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यक्तियों/समूहों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/संस्थानों आदि के लिये इन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की घोषणा करता है। निम्नलिखित को पुरस्कार का वितरण किया जाता है:
  - महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु।
  - पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास हेतु।
  - ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के लिये।
  - सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान और सम्मान आदि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये।
- पात्रता:
  - दिशा निर्देशों के अनुसार, कम-से-कम 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 5 वर्षों तक कार्य करने वाले संस्थान आवेदन करने के पात्र हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

12.

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से 24वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on e-Governance- NCeG)-2021 का आयोजन किया।
  - दो दिवसीय सम्मेलन में आयोजित सत्रों के दौरान गहन विचार-विमर्श के बाद ई-गवर्नेंस समापन में 'हैदराबाद घोषणा-पत्र' (Hyderabad Declaration) को स्वीकार किया गया। अत: विकल्प C सही है।
  - घोषणा का उद्देश्य नागरिकों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा नागरिक सेवाओं को परिवर्तित करना है।
- सम्मेलन ने संकल्प लिया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें निम्नलिखित में सहयोग करेंगी:
  - आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस), ई-हस्ताक्षर और सहमति रूपरेखा सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं में बदलाव।
  - संबद्ध सेवाओं हेतु ओपन इंटर-ऑपरेबल आर्किटेक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से कार्यान्वयन करना।

- सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा के लिये डेटा गवर्नेंस ढाँचे का संचालन करना और नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी डेटा को data.gov.in पर उपलब्ध कराना।

13.

उत्तर: B

व्याख्या:

'प्रारंभ' (Prarambh) शिखर सम्मेलन:

- 'प्रारंभ' (Prarambh) शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा विचारों को नए नवाचारों व आविष्कारों को एक साथ आने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
  - इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के 56 देशों की भागीदारी देखी गई।
- शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है।
- स्टार्टअप्स के लिये अन्य संबंधित पहलें:
  - स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन के लिये समग्र रूप से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और सुधारने के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
  - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - स्टार्टअप इंडिया पहल: इसमें नवोन्मेष को बढ़ावा देने और उभरते उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। अत: विकल्प B सही है।

14.

उत्तर: A

व्याख्या:

- तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
  - तकनीकी वस्त्र उत्पाद की मांग किसी देश के विकास और औद्योगीकरण पर निर्भर करती है।
- तकनीकी वस्त्र परिदृश्य:
  - भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने पिछले पाँच वर्षों में गति पकड़ी है, जो वर्तमान में 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।
    - अगले पाँच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% की सीमा तक ले जाने का लक्ष्य है।
  - मौजूदा विश्व बाज़ार 250 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब अमेरिकी डॉलर है।
  - भारत इस बाज़ार में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8% शेयर) के साथ एक महत्त्वाकांक्षी देश है।
    - सबसे बड़े देश यूएसए, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान (20-40%) हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- वस्त्र उद्योग से संबंधित पहल:
  - कपड़ा क्षेत्र के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP): यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।
  - टेक्नोटेक्स इंडिया: यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसमें वैश्विक तकनीकी कपड़ा मूल्य श्रृंखला के हितधारकों की भागीदारी के साथ प्रदर्शनियाँ, सम्मेलन और सेमिनार शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - तकनीकी वस्त्र के लिये नामकरण प्रणाली (HSN) कोड: सरकार ने वस्त्र निर्माताओं को वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने तथा आयात और निर्यात के आँकड़ों की निगरानी में मदद करने के लिये तकनीकी वस्त्रों हेतु 207 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर' (HSN) कोड प्रदान किये हैं। अत: कथन 1 सही है।

15.

उत्तर: C

व्याख्या:

सारथी:

- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल एप सारथी लॉन्च किया है।
  - 'R' 'र' को व्यक्त करता है।

- इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाज़ार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- यह एप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड (एमएफ), हालिया बाज़ार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा।

प्रतिभूति बाज़ार:

- प्रतिभूतियाँ एक प्रकार का वित्तीय साधन हैं, जो धन जुटाने हेतु जारी किये जाते हैं।
- प्रतिभूति बाज़ारों का प्राथमिक कार्य उन लोगों से पूंजी के प्रवाह को सक्षम करना है, जिनके पास इसकी अधिकता है।
- प्रतिभूति बाज़ार निवेश के लिये धन के आवंटन हेतु चैनल प्रदान करते हैं और इस तरह इन दोनों गतिविधियों को अलग कर देते हैं। अत: विकल्प C सही है।

16.

उत्तर: A

व्याख्या

- हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देश, 2021' को प्रस्तावित किया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- RADPFI 2021 दिशानिर्देश स्थानिक ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है और यह गाँवों में दीर्घकालिक नियोजन हेतु एक परिप्रेक्ष्य विकसित कर ग्रामीण परिवर्तन का मार्ग तैयार करेगा। अत: कथन 2 सही है।
- इन नए दिशानिर्देशों के माध्यम से 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देश, 2017' को संशोधित किया जाएगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

17.

उत्तर: C

व्याख्या:

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
  - प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह संसद के एक अधिनियम तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है।
- इसे निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियां, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास की ज़िम्मेदारी के साथ आज्ञापित किया गया है।
- एपीडा (APEDA) को चीनी के आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।
- अत: विकल्प C सही है।

18.

उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने की योजना चरण- II:

- परिचय:
  - भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवाओं के बुनियादी ढाँचे को सहायता प्रदान करने के लिये भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र- चरण- II में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना को अधिसूचित किया है।
    - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने वाली इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की मज़बूत रचना करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतिशत का योगदान करता है।
- प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु नवंबर 2014 में 'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि' योजना को अधिसूचित किया गया था।
- वित्तीय परिव्यय:
  - इस योजना में 975 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपए के उद्योग योगदान के साथ 1207 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय शामिल है।
- घटक:
  - प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान।
  - चार नए 'उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों' की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार।
  - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिये योग्यता पैकेज बनाना।
  - चार 'कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स' (CEFCs) की स्थापना और मौजूदा CEFCs का संवर्द्धन।

- मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार।
- दस 'इंडस्ट्री एक्सेलरेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट' की स्थापना करना। अत: विकल्प D सही है।

19.

उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनेबलर्स को पहचानना व पुरस्कृत करना जो नवोन्मेषी उत्पादों या समाधानों एवं स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोज़गार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता शामिल है, जो मापन योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं।
- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया है।
  - यह भी घोषणा की गई है कि स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिये 16 जनवरी (स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में इसी दिन शुरू किया गया था) को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
  - विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों एवं कॉरपोरेट्स के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर को जीत की राशि के रूप में 15 लाख रुपए मिलेंगे।
    - 1 इनक्यूबेटर और 1 एक्सेलेरेटर के साथ 46 स्टार्टअप को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अत: विकल्प C सही है।

20.

उत्तर: B

व्याख्या

- हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने ओपन डेटा अपनाने को प्रोत्साहित करने और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये 'ओपन डेटा' सप्ताह शुरू करने की घोषणा की है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान यानी 17 जनवरी, 2022 से 21 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जो जटिल शहरी मुद्दों, जैसे कि कोविड -19 महामारी को संबोधित करने हेतु डेटा के उपयोग और प्रचार को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता हो। अत: कथन 2 सही है।

21.

उत्तर: B

व्याख्या

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum's - WEF) के दावोस एजेंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।
  - दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में WEF की वार्षिक बैठक वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिये विश्व के शीर्ष नेताओं को शामिल करती है।
- प्रो-प्लेनेट पीपुल्स (P3) एप्रोच:
  - वैश्विक मंच (UNFCCC COP 26) में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाले "पी3 (प्रो-प्लैनेट-पीपल) मूवमेंट" के विचार का प्रस्ताव रखा गया।
    - भारत के "स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और विश्वसनीय" ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया गया, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero Carbon Emission) प्राप्त करने पर केंद्रित हैं।
  - LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली- UNFCCC COP-26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई) को एक जन आंदोलन बनाना P3 के लिये एक मज़बूत आधार हो सकता है।
    - LIFE एक लचीली और टिकाऊ जीवनशैली की दृष्टि है जो जलवायु संकट व भविष्य की अन्य अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में काम आएगी।
    - इस संस्कृति और उपभोक्तावाद ने जलवायु चुनौती को बढ़ा दिया है। अत: विकल्प B सही है।

22.

उत्तर: A

व्याख्या:

- देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स (IndiaSkills 2021 Nationals) का हाल ही में समापन हुआ।
  - यह प्रतियोगिता कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिये डिज़ाइन की गई है तथा युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु एक मंच प्रदान करती है।
  - इंडियास्किल्स प्रतियोगिता प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकारों एवं उद्योगों के सहयोग से आयोजित की जाती है।

- वर्ष 2021 में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) ने प्रतियोगिता में भाग लिया तथा 54 विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें सात नए कौशल शामिल थे।
  - कौशल क्षेत्रों में सौंदर्य चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, पुष्प विज्ञान, रोबोट प्रणाली एकीकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग, जल प्रौद्योगिकी, पेंटिंग एवं सजावट, स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
- नोडल एजेंसी:
  - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) इस कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल एजेंसी है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में काम कर रहा है।
    - NSDC 2011 से वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी का नेतृत्त्व कर रहा है।
- ओडिशा इंडियास्किल्स 2021 के चार्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और केरल का स्थान है। अत:कथन 2 सही नहीं है।
  - इंडियास्किल्स 2021 नेशनल्स के विजेताओं को अक्तूबर 2022 में चीन के शंघाई में होने वाली वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्त्व करने का मौका मिलेगा।

23.

उत्तर: C

व्याख्या:

- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) की उत्पत्ति वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और दो प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की स्थापना की। अत: कथन 1 सही है।
- वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ:
  - आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना।
  - वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क को कम करने करना।
- GATT 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन (संस्था नहीं) बन गया जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई।
  - GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल का व्यापार संचालन जारी रखा।
- उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अत: कथन 2 सही है।

24.

उत्तर: A

व्याख्या:

- क्षतिपूरक वनीकरण का अर्थ है हर बार वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु डायवर्ट किया जाना है जैसे खनन या उद्योग, उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र में वन रोपण के लिये भुगतान करना या जब ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो निम्नीकृत वन भूमि के लिये क्षेत्रफल का दोगुना भुगतान करना।
- केंद्र द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम को वर्ष 2016 में पारित और संबंधित नियमों को वर्ष 2018 में अधिसूचित किया गया था।
  - CAF अधिनियम को क्षतिपूरक वनरोपण के लिये एकत्रित धन का प्रबंधन करने हेतु अधिनियमित किया गया था जो तब तक तदर्थ क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) द्वारा प्रबंधित किया जाता था।
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष का 90% राज्यों को देना होता है जबकि 10% केंद्र को अपने पास रखना होता है। अत: कथन 1 सही है।
  - धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गाँवों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, काष्ठ सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।. अत: कथन 2 सही नहीं है।

25.

उत्तर: C

व्याख्या:

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY):

- यह माध्यमिक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है।
- PMJAY के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है।
  - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है।
  - ये दरें लचीली होती हैं, लेकिन वे अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते।

- लाभार्थी: यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। अत: कथन 3 सही है।
  - एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है और वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मान्य हो सकता है।

26.

उत्तर: A

व्याख्या:

- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने सर्विसेज़ ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन (SeHAT) नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत सैनिकों और सैन्यकर्मियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है।
- यह रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों के लिये एक टेलीकंसल्टेशन सेवा है जिसे सभी पात्र सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों हेतु बनाया गया है।
- डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के लिये सरकार की प्रतिबद्धता के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 मई, 2021 को सेहत का शुभारंभ किया।
- इसका उद्देश्य मरीज़ो को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- सेहत स्टे होम ओपीडी ई-संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संचालित एक मुफ्त ओपीडी सेवा पर आधारित है। अत: विकल्प A सही है।

27.

उत्तर: B

व्याख्या:

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System):

- इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इसको वर्ष 2018 में सुव्यवस्थित करने तथा अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी।
- NPS को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही है।
- एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत स्वामित्त्व पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) के पास है।

28.

उत्तर: A

व्याख्या:

- नई रोशनी- अल्पसंख्यक महिलाओं के लिये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग केअल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई थी।
  - इस योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान कर अल्पसंख्यक महिलाओं, उनके पड़ोसियों सहित, एक ही गाँव/इलाकों में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न करना है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की मदद से चलाई जाती है।
- 'नई मंजिल' योजना का उद्देश्य 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुषों और महिलाओं दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में आने वाले लोगों ने मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- उस्ताद (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन): इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

29.

उत्तर: C

व्याख्या

- हाल ही में 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (SERB) ने ग्रीष्मकालीन सत्र के लिये 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना के एक कार्यक्रम 'अभ्यास' के तहत आवेदन आमंत्रित किये हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (SERB) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है।
  - अभ्यास (ABHYAAS): 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका लक्ष्य स्नातकोत्तर (Post-Graduate) एवं पीएचडी के छात्रों को उनके संबंधित विषय में कौशल विकास के लिये प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के दो उप-घटक 'कार्यशाला' (KARYASHALA) और 'वृत्तिका' (VRITIKA) हैं।

- 'एक्सीलेरेट विज्ञान' (AV) योजना वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और एक वैज्ञानिक कार्यबल तैयार करने का प्रयास करती है, जो अनुसंधान कॅरियर और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में उद्यम कर सके।
  - 'एक्सीलेरेट विज्ञान' (AV) योजना का लक्ष्य देश में अनुसंधान आधार का विस्तार करना है, जिसमें तीन व्यापक लक्ष्य शामिल हैं- सभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समेकन/एकत्रीकरण, हाई-एंड अभिविन्यास कार्यशालाएँ शुरू करना और प्रशिक्षण एवं कौशल इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना। अत: कथन 2 सही है।

30.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय रेलवे, जो हर दिन (महामारी से पहले) 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है उन संदिग्धों के लिये सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे विश्वसनीय वाहक है, जो बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं।
- ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) के तहत बुनियादी ढाँचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, गंतव्य, संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों/एजेंटों, किंगपिन आदि की पहचान करने और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, उनके मिलान एवं विश्लेषण करने हेतु किया जा सकता है।
- इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने में स्थानीय पुलिस की सहायता हेतु राज्यों में एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है।
- इसके अलावा साइबर सेल द्वारा मानव तस्करी के डिजिटल तरीको की तलाश हेतु वेब/सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही नेपाल, बांग्लादेश तथा म्याँमार की सीमा से लगे ज़िलों से आने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अत: विकल्प A सही है।

31.

उत्तर: C

व्याख्या:

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम:

- इसका उद्देश्य देश में विज्ञान-प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम-प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। अत: कथन 1 सही है।
- पहले कदम के रूप में 'विज्ञान ज्योति' को वर्ष 2019-20 में स्कूल स्तर पर शुरू किया गया था, जिसमें कक्षा 9-12 की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा में STEM पाठ्यक्रमों को अपनाने और इसमें कॅरियर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- विज्ञान ज्योति द्वारा स्कूल स्तर यानी कक्षा IX से ही मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है जो पीएचडी स्तर तक जारी रहेगा ताकि लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे उनके कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में कॅरियर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। अत: कथन 2 सही।
- नवोदय विद्यालय समिति (NVS), शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है जो विज्ञान ज्योति का कार्यान्वयन भागीदार है। NVS का भारत के 600 से अधिक ज़िलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) का नेटवर्क है।

32.

उत्तर: C

व्याख्या:

मिशन इंद्रधनुष:

- इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं।
- मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, क्षय, हेपेटाइटिस-बी, मैनिन्जाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण, जापानी एनसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा-रूबेला शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - जापानी एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन देश के चुनिंदा ज़िलों में किया जा रहा है।
- मिशन इंद्रधनुष को भी ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया था। अत: कथन 2 सही है।

33.

उत्तर: C

व्याख्या:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

- वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
  - इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को प्रतिस्थापित किया।

- उद्देश्य: फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।
- दायरा: वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं। अत: कथन 1 सही है।
- प्रीमियम: इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है। अत: कथन 2 सही है।
  - किसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया गया था।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है।
- कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार बोली के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी (IA) का चयन करती है।

संशोधित PMFBY: संशोधित PMFBY को अक्सर PMFBY 2.0 कहा जाता है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- पूर्ण रूप से स्वैच्छिक: वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है।
  - इससे पहले अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिये यह योजना अनिवार्य थी।
- केंद्रीय सब्सिडी की सीमा: कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों हेतु 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया जाता है।
- राज्यों को अधिक नम्यता: सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प दिया है।
- IEC गतिविधियों में निवेश: बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होता है।

34.

उत्तर: A

व्याख्या:

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।
  - PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अत: कथन 1 सही है।
  - जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।
- पात्रता:
  - एक असंगठित श्रमिक (UW) होना चाहिये।
  - मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम।
  - प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये।
  - नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो।
  - आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

35.

उत्तर: C

व्याख्या:

- SAMPANN (सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) परियोजना को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिये एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है।
  - यह पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट प्रदान करता है।
  - यह संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
  - इस प्रणाली ने विभाग को पेंशन मामलों के तेज़ी से निपटान, बेहतर समाधान/लेखापरीक्षा और लेखांकन को आसान बनाने में मदद की है।
  - इसके द्वारा 6 महीने की अल्प अवधि में ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के करीब 76,000 मामलों को निपटाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- यह एक लचीली डिज़ाइन वाली प्रणाली है जो इसे लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाती है। अत: विकल्प C सही है।

36.

उत्तर: B

व्याख्या:

- अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएँ
  - यह अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। जिसे पहली बार वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।
  - हुनर हाट की अवधारणा वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की कला और शिल्प की पैतृक विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिये की गई है। अत: युग्म 3 सही सुमेलित है।
  - बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति: इस छात्रवृत्ति योजना के तहत छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन) की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  - गरीब नवाज़ रोज़गार योजना: केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से जुड़े युवाओं के लिये रोज़गारपरक अल्पावधि कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी।
  - नई मंज़िल:'नई मंजिल' औपचारिक स्कूल शिक्षा और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के कौशल विकास की एक योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त, 2015 को हुई थी।अत: युग्म 1 सही सुमेलित है।
  - उस्ताद (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development): इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है।अत: युग्म 2 सुमेलित नहीं है।
  - नई रोशनी: अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्त्व क्षमता विकास करना।

37.

उत्तर: D

व्याख्या:

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने मिलकर इस क्षेत्र के विकास को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करने के लिये कई पहल की हैं।
  - MSME क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिये बीईई और एमएसएमई मंत्रालय ने एक सहयोगी मंच - "समीक्षा" (लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा दक्षता ज्ञान साझाकरण) को भी बढ़ावा दिया है।
    - मंच का उद्देश्य ज्ञान को एकत्र करना और स्वच्छ, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तथा प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने के लिये विभिन्न संगठनों के प्रयासों में तालमेल बिठाना है। अत: विकल्प D सही है।

38.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के साथ एकीकृत 'विहंगम (VIHANGAM)' नामक एक इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है।
- इस प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS), एक RPAS, 40 Mbps की इंटरनेट लीज़ लाइन और विहंगम पोर्टल शामिल हैं।
  - यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक वास्तविक समय में प्रसारित करने में सक्षम बनाती है, जिसे केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा ही विहंगम पोर्टल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
  - अत: विकल्प D सही है।

39.

उत्तर: B

व्याख्या:

- डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है।
  - यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- डंपिंग-रोधी शुल्क का अधिरोपण वस्तुओं की डंपिंग और उसके व्यापार विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने का एक उपाय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:
  - ADD आयात पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है।

- लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाया जाता है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है। अत: कथन 2 सही है।

40.

उत्तर: D

व्याख्या:

- जननी सुरक्षा योजना: जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिये चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी) पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया गया है।
- लक्ष्य कार्यक्रम: लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। अत: कथन 2 सही है।
- पोषण अभियान: पोषण अभियान का लक्ष्य बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। अत: कथन 3 सही है।

41.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ ने संस्थानों की 'नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग' (ARIIA) 2021 जारी की।
- ARIIA का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी हुआ था।
- यह छात्रों तथा संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की एक संयुक्त पहल है। अत: कथन 2 सही है।
  - ARIIA नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न वास्तविक प्रभाव को मापने का प्रयास करता है।
- रैंकिंग तकनीकी और गैर-तकनीकी दो श्रेणियों के तहत बनाई गई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - तकनीकी श्रेणी में 5 उप-श्रेणियाँ शामिल हैं -
    - केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान(CFTIs), केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान
    - राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय (सरकारी और सरकारी द्वारा सहायता प्राप्त)
    - सरकारी कॉलेज/संस्थान (सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त)
    - विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय (स्व-वित्त / निजी)
    - निजी कॉलेज/संस्थान (स्व-वित्त/निजी)
  - गैर-तकनीकी श्रेणी में दो उप-श्रेणियाँ शामिल हैं-
    - केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान (CFIs)/ केंद्रीय विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय महत्त्व के गैर-तकनीकी संस्थान।
    - सामान्य (गैर-तकनीकी)।

42.

उत्तर: B

व्याख्या:

- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) को नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड -19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोज़गार के अवसरों के सृज़न को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization - EPFO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिये भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।

43.

उत्तर: A

व्याख्या:

- वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'प्रोजेक्ट सनराइज़' लॉन्च किया गया था, जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में, विशेष रूप से ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के बीच बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने के लिये है।
- इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की मौजूदा परियोजनाओं के अलावा उत्तर पूर्व में लागू किया जाएगा।
- अत: विकल्प A सही है।

44.

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY-II) का पहला चरण गरीब परिवारों को 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस' (LPG) कनेक्शन प्रदान करने के लिये मई 2016 में शुरू किया गया था।
  - PMUY-II को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं तथा अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
    - अब उन्हें इसका लाभ उठाने के लिये केवल "सेल्फ डिक्लेरेशन" देना होगा।
- इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - एक जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉटप्लेट नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
- उज्जवला योजना के लिये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) नोडल मंत्रालय है।
- अत: विकल्प B सही है।

45.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भाषा संगम:
  - यह 22 भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची की भाषाएँ) के दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सिखाने के लिये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया है। अत: कथन 2 सही है।
  - इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधी कौशल हासिल करना चाहिये।
    - यह दीक्षा, ई-पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
- शुरू की गई अन्य पहलों में भाषा संगम मोबाइल एप और एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) क्विज़ एप शामिल हैं।

46.

उत्तर: C

व्याख्या:

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सड़कों और पुलों के निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I और II (PMGSY-I और II) को सितंबर 2022 तक जारी रखने हेतु अपनी मंज़ूरी दे दी है।
- PMGSY-I जनगणना-2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु वर्ष 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। अत: कथन 1 सही है।
- इस योजना में पात्र बसावटों वाले उन सभी ज़िलों के लिये मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के घटक भी शामिल थे। अत: कथन 2 सही है।

47.

उत्तर: A

व्याख्या:

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण:

- लॉन्च: वर्ष 2022 तक "सभी के लिये आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना- इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी के रूप में पुनर्गठित किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- शामिल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के ग्रामीण लोगों को आवासीय इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

- लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति व अल्पसंख्यक। अत: कथन 3 सही है।

48.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिये नई योजना 'भारत गौरव' की घोषणा की है। अत: विकल्प A सही है।
- योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिये तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे।
- ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारिणी के अनुसार चलेंगी बल्कि आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी।

49.

उत्तर: C

व्याख्या:

- एक्रॉस योजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। अत: कथन 1 सही है ।
- यह योजना मौसम, जलवायु एवं समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान एवं सेवाएँ और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगी। इसमें चक्रवात, तूफानी लहरों, हीट वेव और तड़ित झंझा से संबंधित चेतावनी शामिल होगी। अत: कथन 2 सही है।
- पूर्वानुमान से जुड़ी सूचनाओं को तैयार करने से लेकर इनके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर काफी संख्या में श्रमशक्ति की ज़रूरत होती है, जिससे कई लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।

50.

उत्तर: A

व्याख्या:

- स्वदेश पहला बड़े पैमाने वाला मल्टीमॉडल न्यूरोइमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों (दिये गए चित्र) के लिये बड़े डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय आबादी हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- इस योजना में एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर है जो 6 मॉड्यूल्स के प्रबंधन और विश्लेषण का प्रस्ताव करता है। इन मॉड्यूल्स में शामिल हैं- न्यूरोडिजेनेरेटिव [एडी, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट (MCI), पार्किंसंस रोग (PD)], न्यूरोसाइकाइट्रिक (सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार), न्यूरोडेवलपमेंटल (ऑटिज़्म व मिर्गी), कोविड-19 से संबंधित बीमारियाँ तथा अन्य विकार।
- स्वदेश जावा आधारित वर्कफ्लो वातावरण और पायथन से युक्त है जो इसे गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट और डेटा बैकअप उपलब्ध कराता है।
  - पायथन और जावा दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएँ हैं। अत: विकल्प A सही है।

51.

उत्तर: B

व्याख्या:

- जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज एलायंस (RCA) को लॉन्च किया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह भारत में नदी शहरों के लिये शहरी नदियों के सतत् प्रबंधन हेतु विचार, चर्चा और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिये एक समर्पित मंच है। अत: कथन 2 सही है।

52.

उत्तर: A

व्याख्या

- हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिये 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 'दुआरे राशन' (घर के दरवाज़े पर राशन) योजना शुरू की है। अत: विकल्प A सही है।

53.

उत्तर: B

व्याख्या:

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे कुल 950 करोड़ रुपए की लागत से 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- इसे भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करने के लिये विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगी, जिसमें अलग-अलग राज्य अपनी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार प्रासंगिक और उचित चीज़ो को जोड़ सकेंगे।
- कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS), ULPIN, राजस्व न्यायालयों को भूमि अभिलेखों से जोड़ने, सहमति आधारित आधार संख्या को भूमि अभिलेखों के साथ जोड़ने आदि जैसी नई पहल की गई है।

54.

उत्तर: D

व्याख्या:

- ASER सर्वेक्षण ग्रामीण शिक्षा एवं सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जिसमें पढ़ने एवं अंकगणितीय कौशल को शामिल किया गया है। इसे पिछले 15 वर्षों से NGO प्रथम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत शिक्षा के स्तरों पर प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि की श्रेणी हेतु सबसे बेहतर माना जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

55.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष (1997) के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना की स्थापना की गई थी।
- यह एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले चयनित युवा वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। अत: कथन 1 सही है।
- इस पुरस्कार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 5 साल की अवधि के लिये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अनुसंधान अनुदान के साथ मूल संस्थान से प्राप्त वेतन के अलावा 25000 रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप शामिल है।
- पुरस्कार के लिये चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ स्वतंत्र अनुसंधान करने की अनुमति है।
  - परियोजना में नवीन अनुसंधान विचार शामिल होने चाहिये और इनमें अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिये।
- चयनित अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के मानदंडों के आधार पर वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
  - SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। अत: कथन 3 सही है।

56.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'सीनियर एबल सिटीज़न फॉर रि-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी' (SACRED) पोर्टल विकसित किया है।
  - 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और रोज़गार तथा कार्य अवसर के लिये आवेदन कर सकते हैं।
  - 'रोज़गार पोर्टल' न केवल रोज़गार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, बल्कि नियोक्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), कौशल प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और अन्य एजेंसियों या व्यक्तियों को भी सेवा प्रदान करेगा।
- अन्य पहलें:
  - एल्डर लाइन': यह वरिष्ठ नागरिकों के लिये पहला अखिल भारतीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14567) है।
  - सेज (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पोर्टल: यह विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला 'वन-स्टॉप एक्सेस' होगा। अत: विकल्प D सही है।

57.

उत्तर: C

व्याख्या:

- 'पाक बे योजना' जिसे 'डायवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राउल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट्स इनटू डीप सी फिशिंग बोट्स' के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2017 में 'केंद्र प्रायोजित योजना' के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसे 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- यह तमिलनाडु-विशिष्ट योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को तीन वर्ष में 2,000 जहाज़ उपलब्ध कराना और उन्हें 'बॉटम ट्रालिंग' छोड़ने के लिये प्रेरित करना है। अत: कथन 2 सही है।
  - 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक संबद्ध गतिविधि के रूप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
- इस योजना का एक अन्य उद्देश्य 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा' (IMBL) के आसपास 'मत्स्य पालन के दबाव को कम करना' है, ताकि तमिलनाडु के मछुआरे 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा' को पार करते हुए श्रीलंकाई जल में न चले जाएँ।

58.

उत्तर: B

व्याख्या

- हाल ही में सरकार ने 'संकल्प' (स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन) प्रोग्राम के तहत 'महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप' के दूसरे चरण की शुरुआत की है। अत: कथन 1 सही है।
- यह दो वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम है, जो ज़मीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान देकर युवाओं के लिये अवसर पैदा करता है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह विश्वसनीय योजना बनाने, रोज़गार तथा आर्थिक उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने में बाधाओं की पहचान करने हेतु ज़िला स्तर पर अकादमिक भागीदार आईआईएम के माध्यम से कक्षा सत्रों को व्यापक स्तर पर ज़मीनी सर्वेक्षण के साथ संयोजित करने का प्रयास करता है।
  - स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकसित करने पर ध्यान देना 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन देता है और एक उद्योग-प्रासंगिक कौशल आधार का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मददगार होगा।
- फेलोशिप हेतु 21-30 वर्ष आयु-समूह के युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। अत: कथन 3 सही नहीं है।

59.

उत्तर: A

व्याख्या:

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- किरण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार व अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है।
- मनोदर्पण पहल: यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये सभी सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाती है। अत: विकल्प A सही है।

60.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम- "संभव", 2021 की शुरुआत की।
- यह बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचने के लिये MSME मंत्रालय के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय, देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों/ आईटीआई के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।
  - इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो/वीडियो फिल्म के माध्यम से MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।
- इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्यमिता तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये युवाओं को भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करना। अत: विकल्प A सही है।

61.

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्वदेश दर्शन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था।
  - इस योजना की परिकल्पना अन्य योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये की गई है।
- इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करता है।
- पर्यटक सर्किट: इस योजना के तहत पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है-
  - बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेज़र्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट।
  - अत: विकल्प D सही है।

62.

उत्तर: D

व्याख्या:

- शिक्षक पर्व 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इन पहलों में शामिल है:
  - निपुण भारत हेतु निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- 'नेशनल इनिसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट' (NISHTHA) एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
- निपुण (बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल) भारत योजना को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने हेतु शुरू किया गया था, ताकि ग्रेड-3 तक का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। अत: युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

- विद्यांजलि 2.0 पोर्टल: इसे विद्यालय विकास हेतु शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं और CSR (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) योगदानकर्ताओं की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रारंभ किया गया था।
  - विद्यांजलि योजना उन अभिनव योजनाओं में से एक है जो सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षकों की पेशकश करके साक्षरता में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करती है। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। अत: युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये प्रधानमंत्री ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लॉन्च किया जो उच्च शिक्षा में छात्रों को प्रवेश और निकास के कई विकल्प प्रदान करने के साथ ही प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।
  - शुरू की गई पहलों में विद्या प्रवेश (Vidya Pravesh) पहल भी शामिल है, जो ग्रेड 1 के छात्रों के लिये नाटक/प्ले आधारित तीन माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल (School Preparation Module) है, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, NISHTHA 2.0, NCERT द्वारा डिज़ाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण का एक एकीकृत कार्यक्रम है और SAFAL (सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिये संरचित मूल्यांकन), जो कि सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिये एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढाँचा है। अत: युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।
  - इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम (NETF) का शुभारंभ भी हुआ।

63.

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत द्वारा आयोजित और मेज़बानी किये जाने वाले कार्यक्रमों की एक वैश्विक श्रृंखला का हिस्सा है, ताकि भारतीय और वैश्विक नेताओं एवं अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जा सके, जो समावेशी, टिकाऊ और जलवायु समर्थित भारतीय शहरों को डिज़ाइन करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
  - WRI India एक स्वतंत्र चैरिटी संस्थान है, जो कानूनी रूप से 'इंडिया रिसोर्सेज़ ट्रस्ट' के रूप में पंजीकृत है।
- 'कनेक्ट करो' विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुतकर्त्ताओं का अवलोकन करता है, जैसे-वायु प्रदूषण, विद्युत गतिशीलता, शहरी नियोजन, शहरी जल लचीलापन, जलवायु शमन और सार्वजनिक पारगमन एवं दूसरों के बीच अपनी अंतर्दृष्टि तथा शोध निष्कर्षों को साझा करना। अत: विकल्प A सही है।

64.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) तथा RMI इंडिया द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की डिलीवरी को अपनाने में तेजी लाना और उपभोक्ताओं एवं उद्योगों के साथ साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों (Zero-Pollution Delivery Vehicles) को बढ़ावा देना है। अत: कथन 1 सही है।
- इस अभियान के हिस्से के रूप में अंतिम बिंदु तक डिलीवरी के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की दिशा में उद्योग जगत के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने हेतु कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एवं प्रमाणन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
  - यह ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्द्धियों से अलग करने में मदद करेगा।
- एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में विद्युतीकृत किलोमीटर, कार्बन संबंधी बचत, मानक प्रदूषक संबंधी बचत और स्वच्छ डिलीवरी वाहनों से होने वाले अन्य लाभों से जुड़े आँकड़ों के माध्यम से इस अभियान के प्रभावों को साझा करेगा।

65.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये SPIN (Strengthening the Potential of India- भारत की क्षमता को मज़बूत करना) योजना शुरू की है।
  - SPIN के तहत KVIC कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। अत: कथन 1 सही है।
- SPIN का उद्देश्य स्थानीय स्वरोज़गार का निर्माण करके सतत् विकास करना है जो प्रधानमंत्री की "हर हाथ से नौकरी" (हर हाथ में काम) की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
  - यह एक नो-सब्सिडी कार्यक्रम है।
- KVIC कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

66.

उत्तर: B

व्याख्या:

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन:

- इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने में सहायता करने के लिये डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी।
- यह पायलट परियोजना छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप में लागू की जा रही है।
- स्वास्थ्य आईडी प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में हर परीक्षण, हर बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होगा। अत: कथन 2 सही है।
- स्वास्थ्य आईडी नि:शुल्क व स्वैच्छिक है। यह स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट और कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

67.

उत्तर: D

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री पोषण योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिये भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
  - यह योजना स्कूलों में मिड-डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी।
- इस योजना के तहत सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिये कई पहल शुरू की हैं। उदाहरण के लिये:
  - पोषाहार उद्यान:
    - इसके तहत सरकार, स्कूलों में 'पोषाहार उद्यानों' को बढ़ावा देगी। छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किये जायेंगे। अत: कथन 1 सही है।
  - पूरक पोषण:
    - नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है। अत: कथन 2 सही है।
- यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियों के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करता है।
- वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को हटा लिया गया है।
  - तिथि भोजन की अवधारणा:
    - तिथिभोजन (Tithi Bhojan) की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। अत: कथन 3 सही है।
    - तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं।

68.

उत्तर: C

व्याख्या:

- MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
  - इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (सांसद) को अवसंरचना के निर्माण पर ज़ोर देने के साथ स्थानीय स्तर की ज़रूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों का सुझाव देने और निष्पादित करने में सक्षम बनाना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- प्रारंभ में यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में था। बाद में अक्तूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत स्थानांतरित कर दिया गया। अत: कथन 2 सही है।
- MPLAD के तहत जिला प्राधिकारियों को जारी की गई धनराशि व्यपगत नहीं होती है, जबकि किसी विशेष वर्ष में सरकार द्वारा जारी नहीं की गई धनराशि को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अत: कथन 3 सही है।

69.

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) है। यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार है।
- इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है जो न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अत: कथन 1 सही है।
- लेटरल एंट्री मैकेनिज्म मिशन कर्मयोगी से अलग सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिये सुधार है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- क्षमता निर्माण iGOT-कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार की गई सामग्री होगी।

70.

उत्तर: C

व्याख्या:

- इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह भारत सरकार के 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। हालाँकि लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है। अत: कथन 2 सही है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अत: कथन 3 सही है।

71.

उत्तर: C

व्याख्या :

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल 'उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण' (Training for Augmenting Productivity and Services- TAPAS) लॉन्च किया है।
  - यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिये सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD) की एक पहल है।
  - यह एक मानक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री होती है।
- प्लेटफॉर्म को वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन के चतुर्भुज दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है।
  - पाँच बुनियादी कोर्स जैसे- नशीली दवाओं (पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा/बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- अन्य डिजिटल लर्निंग पहल:
  - स्वयं (SWAYAM) : ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई, 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) लॉन्च किया गया था।
  - स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) : यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
  - प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) : इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है। अत: विकल्प C सही है।

72.

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा संयंत्रों, सौर कृषि जल पंपों तथा मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण का प्रावधान है। अत: कथन 1 सही है।

- चूँकि किसान सब्सिडी वाली बिजली पर कम निर्भर होंगे, पीएम-कुसुम योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय सशक्तीकरण का समर्थन करेगी। अत: कथन 2 सही है।
- यह योजना वर्ष 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी। अत: कथन 3 सही नहीं है।

73.

उत्तर: C

व्याख्या:

- JSS की योजना को पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, यह भारत सरकार की एक अनूठी योजना थी और इसे वर्ष 1967 से देश में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से लागू किया गया था।
  - वर्ष 2000 में इस योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान (JSS) कर दिया गया।
- इसे जुलाई 2018 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- JSS न्यूनतम लागत और बुनियादी ढाँचे के साथ लाभार्थियों को उनके दरवाज़े पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर लाभान्वित कर रहे हैं। अत: कथन 1 सही है।
- JSS इस अर्थ में अद्वितीय हैं कि वे न केवल व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हैं बल्कि इसमी जीवन कौशल को भी शामिल करते हैं जो लाभार्थी को दैनिक जीवन में मदद कर सकता है।
- प्राथमिकता समूह में महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं।
- इसे भारत सरकार के 100% अनुदान के साथ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। JSS सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अत: कथन 2 सही है।
- जन शिक्षण संस्थान के मामलों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- JSS का कार्य-क्षेत्र: व्यावसायिक तत्त्वों, सामान्य जागरूकता और जीवन संवर्द्धन घटकों को शामिल करते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।

74.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि (समृद्ध) के लिये MeitY के स्टार्टअप एक्सीलेरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अत: कथन 1 सही है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप के लिये एक अनुकूल मंच तैयार करना है ताकि वे अपने उत्पादों को बढ़ा सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिये निवेश सुरक्षित कर सकें। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा किया जा रहा है।
  - MSH एक राष्ट्रीय समन्वय, सुविधा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है जो MeitY के सभी इन्क्यूबेशन केंद्रों, स्टार्टअप और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करेगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप के विकास को आगे बढ़ाना है, जिसमें 63 यूनिकॉर्न सामने आए हैं, जो अब 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है।

75.

उत्तर: B

व्याख्या:

- इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
  - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह भारत सरकार के 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। अत: कथन 1 सही है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। अत: कथन 2 सही है।
  - इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- लाभार्थियों की पहचान:
  - लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

76.

उत्तर: D

व्याख्या:

- एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme- ICDS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child

Development) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित (न कि केंद्रीय क्षेत्र की) योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। अत: कथन 2 सही नहीं है।

- ICDS का उद्देश्य :
  - 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
  - बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
  - मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
  - बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
  - माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना।
  - किशोर लड़कियों (AGs) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें।
- अत: स्पष्ट है कि इस योजना का उद्देश्य न केवल 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, बल्कि बच्चे तथा मातृ स्वास्थ्य से संबंधित अन्य पहलूओं पर ध्यान देना भी है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

77.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के लिये एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप "मत्स्य सेतु" लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश में जलीय कृषि करने वाले किसानों तक ताज़े पानी से संबंधित नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है।
  - शफरी (जलीय कृषि उत्पादों के लिये प्रमाणन योजना): यह अच्छी जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिये गुणवत्तापूर्ण एंटीबायोटिक मुक्त झींगा उत्पादों का उत्पादन में मदद करने हेतु हैचरी के लिये एक बाज़ार आधारित उपकरण है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन और हार्वेस्टिंग को एक्वाकल्चर कहते हैं। अत: कथन 2 सही है।

78.

उत्तर: C

व्याख्या:

- 'संकल्प से सिद्धि' पहल, जिसे 'मिशन वन धन' के रूप में भी जाना जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा भारत की आदिवासी आबादी के लिये एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- इस मिशन के माध्यम से TRIFED का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करना तथा विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों को मिशन मोड में लॉन्च करना है।
- इस मिशन के माध्यम से कई वन धन विकास केंद्रों (VDVKs), हाट, बाज़ारों, मिनी TRIFOOD इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों, TRIFOOD पार्कों, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये फंड की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI), समूहों, ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर, ई-कॉमर्स की स्थापना, ट्राइफूड एवं जनजातियों के लिये मंच और भारतीय ब्रांडों को लक्षित किया जा रहा है।
- TRIFED आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिये कई उल्लेखनीय कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। अत: कथन 2 सही है।
  - भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया।
  - यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  - इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला- लघु वन उपज (Minor Forest Produce (MFP) विकास, दूसरा- खुदरा विपणन एवं विकास (Retail Marketing and Development)।

79.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने संयुक्त रूप से स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण (School Innovation Ambassador Training Program- SIATP) की शुरुआत की। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक आदि-प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है जो प्रशिक्षण इनपुट का भंडार भी है।

- स्कूली शिक्षकों के लिये अभिनव और अपनी तरह के अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), डिज़ाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह छात्रों को भविष्य के लिये तैयार करने हेतु शिक्षकों को परिवर्तन-एजेंट और नवाचार दूत बनाएगा।
- कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिये "उच्च शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्यों हेतु नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर डिज़ाइन किया गया है।
  - प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। अत: कथन 3 सही है।

80.

उत्तर: C

व्याख्या:

- कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra- KVK) भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है। ये केंद्र आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े ICAR और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा व्यावहारिक कृषि अनुसंधान को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं।
  - यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (National Agricultural Research System- NARS) का अभिन्न अंग है। अत: कथन 1 सही है।
  - पहला KVK वर्ष 1974 में पुद्दुचेरी में स्थापित किया गया था।
- KVK का अधिदेश इसके अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा प्रदर्शन है।
  - KVK भी गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पादों जैसे- बीज, रोपण सामग्री, पशुधन आदि का उत्पादन करते हैं और इसे किसानों को उपलब्ध कराते हैं।
- KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा कृषि में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा स्वीकृत हैं। अत: कथन 2 सही है।

81.

उत्तर: C

व्याख्या:

- मध्याह्न भोजन योजना (शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक केंद्र प्रायोजित योजना (न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना) है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
  - एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है।
- यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन।
- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे और मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित हैं। अत: कथन 2 सही है।

82.

उत्तर: D

व्याख्या:

- देशद्रोह कानून को मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) को लागू करते समय इस प्रावधान को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- केदार नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि अगर कानून द्वारा स्थापित सरकार को उलट दिया जाता है तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हालाँकि यह कहा गया है कि धारा 124A केवल उन अभिव्यक्तियों पर लागू होगी जो या तो हिंसा का इरादा रखती हैं या जिनमें हिंसा कराने की प्रवृत्ति है। अत: कथन 3 सही है।

83.

उत्तर: C

व्याख्या:

सहकारिता से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान:

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगर पालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा है।
- संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)" के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है। अत: कथन 1 सही है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy- भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। अत: कथन 2 सही है।
- राज्य सूची की प्रविष्टि 32: सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा निगमों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और संघ; सहकारी समितियाँ।

84.

उत्तर: D

व्याख्या :

- हाल ही में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा "स्थायी आवास के लिये लक्ष्य: ऊर्जा दक्षता निर्माण में नई पहल 2021" (Aiming for Sustainable Habitat: New Initiatives in Building Energy Efficiency 2021) शुरु की गई।
  - ये पहल भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का प्रयास करती हैं और इन्हें 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अत: कथन 3 सही है।
- शुरू की गई पहलें:
  - ईको निवास संहिता 2021 : भारत के ऊर्जा संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु आवासीय भवनों (Energy Conservation Building Code for Residential- ECBC-R) के लिये यह एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है। अत: कथन 1 सही है।
    - यह ईको निवास संहिता 2021 के साथ कोड अनुपालन दृष्टिकोण और भवन सेवाओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन आवश्यकताओं एवं सत्यापन ढाँचें को निर्दिष्ट करता है।
  - हैंडबुक फॉर लर्निंग: वेब आधारित एक मंच "द हैंडबुक ऑफ रेप्लिकेबल डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिसिएंट रेज़िडेन्शियल बिल्डिंग्स" उपलब्ध होगा जिसका उपयोग भारत में कम ऊर्जा खपत वाले भवनों के निर्माण में एक उपयोगी और अपनाई जा सकने योग्य सूचनाओं एवं जानकारियों के स्रोत के रूप में किया जा सकेगा।
  - निर्माण सामग्री की ऑनलाइन डॉयरेक्टरी: ऊर्जा दक्षता वाले भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण सामग्री के लिये मानकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से भवन निर्माण सामग्री की एक ऑनलाइन डॉयरेक्टरी तैयार की जाएगी।
  - निर्माण पुरस्कार: निर्माण पुरस्कार (NEERMAN यानी नेशनल एनर्जी एफिसिएन्सी रोडमैप फॉर मूवमेंट टूवड्र्स एफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबीटेट) की घोषणा की जाएगी जिसका उद्देश्य BEE की ऊर्जा बचत भवन संहिता के अनुरूप तैयार असाधारण रूप से ऊर्जा बचत भवन प्रारूपों को प्रोत्साहित करना है। अत: कथन 2 सही है।

85.

उत्तर: A

व्याख्या:

- मिशन पूर्वोदय को वर्ष 2020 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु लॉन्च किया गया था।
  - इस मिशन के तहत भारत के पूर्वी राज्यों (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो सामूहिक रूप से देश के लौह अयस्क का ~ 80%, कोकिंग कोल का ~ 100% और क्रोमाइट, बॉक्साइट और डोलोमाइट के भंडार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं।
- एकीकृत इस्पात केंद्र 3 प्रमुख तत्त्वों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
  - ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना को आसान बनाकर उनकी क्षमता वृद्धि करना।
  - एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ माँग केंद्रों के पास इस्पात समूहों का विकास करना।
  - रसद और उपयोगिताओं के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन जो पूर्व में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। अत: विकल्प A सही है।

86.

व्याख्या : C

व्याख्या :

- हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा 'गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील' बनाने पर एक नई क्षमता निर्माण पहल का शुभारंभ किया गया। अत: कथन 1 सही है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा बेसिन शहरों में बेहतर नदी स्वास्थ्य के लिये स्थायी शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु क्षमता निर्माण तथा कार्रवाई व अनुसंधान करना है।
- मुख्य केंद्रित क्षेत्र :
  - जल संवेदनशील शहरी डिज़ाइन और योजना।
  - शहरी जल दक्षता और संरक्षण।
  - विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन और स्थानीय रूप से इसका पुन: उपयोग।
  - शहरी भूजल प्रबंधन।
  - शहरी जल निकाय/झील प्रबंधन ।
- अभिसरण प्रयास:
  - इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रमुख शहरी मिशनों और अन्य मिशनों के साथ नमामि गंगे मिशन का अभिसरण सुनिश्चित करना है। अत: कथन 2 सही है।
  - अमृत, स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
  - समस्त गंगा बेसिन राज्यों में राज्य/शहर स्तर पर अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान।

87.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "स्माइल-आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" नामक योजना तैयार की है।
- भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिये मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है।
- यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिये भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुनिश्चित करती है।
  - मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किये जाएंगे।
- इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़, शिक्षा, कौशल विकास आदि हैं।
  - अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लाभान्वित किया जाएगा।
- इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।
- अत: विकल्प A सही है।

88.

उत्तर: B

व्याख्या :

- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (HCDP) एक केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचान किये गए बागवानी क्लस्टर को विकसित करना है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा बनाया जा सके। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।
- बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) शुरू किया है। अत: कथन 2 सही है।
- भारत बागवानी फसलों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो दुनिया के फलों और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 12% है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - भारत केला, आम, अनार, चीकू (Sapota), नींबू, आँवला जैसे फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

89.

उत्तर: C

व्याख्या:

- कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Funds- EPF) योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाली प्रमुख योजना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संस्थागत भविष्य निधि प्रदान करती है।
- कर्मचारी के मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 12% कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही EPF में जमा करते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% EPFO में जमा करने या इसे वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प को चुनने अनुमति दी जाए।
- यह योजना उन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपए तक है। अत: कथन 3 सही है।

90.

उत्तर: A

व्याख्या:

- 'एक राष्ट्र एक मानक' मिशन के विचार की कल्पना पहली बार वर्ष 2019 में की गई थी, इसकी परिकल्पना देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिये 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना की तर्ज पर की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- हाल ही में भारतीय रेलवे का 'अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन' (RDSO) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 'एक राष्ट्र एक मानक' मिशन के तहत 'मानक विकास संगठन' (SDO) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।
  - भारत सरकार के 'एक राष्ट्र एक मानक' विज़न के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत 'मानक विकास संगठन' (SDO) की मान्यता प्रदान की जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - यह मान्यता 3 वर्ष के लिये वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

91.

उत्तर: C

व्याख्या:

- मेगा फूड पार्क योजना (Mega Food Park Scheme) वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके और आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपव्यय को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह योजना "क्लस्टर" दृष्टिकोण पर आधारित है जो एक अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति शृंखला के साथ औद्योगिक भूखंडों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये एक अच्छी तरह से परिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना करती है। अत: कथन 2 सही है।
- इसका उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ता और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ने के लिये एक तंत्र प्रदान करना है ताकि मूल्यवर्द्धन को अधिक, अपव्यय को कम तथा किसानों की आय को ज़्यादा करके रोज़गार के नए अवसर (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में) सुनिश्चित किये जा सकें। अत: कथन 3 सही है।

92.

उत्तर : C

व्याख्या :

- हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिये 'सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन' (SAGE) पहल तथा पोर्टल का शुभारंभ किया है। अत: कथन 1 सही है।
  - रजत (Silver) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
  - सेज पोर्टल (SAGE Portal) विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला 'वन-स्टॉप एक्सेस' होगा।
  - यह ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिये सेवाएँ मुहैया कराने संबंधी क्षेत्र में रुचि रखने वाले उद्यमियों को सहयोग प्रदान करते हो।
- रजत अर्थव्यवस्था (Silver Economy) वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और वरिष्ठ लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना और उनके उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करना है। अत: कथन 2 सही है।
  - रजत अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक जेरोन्टोलॉजी (Gerontology, आयु का अध्ययन) के क्षेत्र में एक मौजूदा आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं किया जाता है बल्कि आयु वृद्धि की नीति के एक साधन के रूप में तथा उनकी आबादी हेतु एक संभावित जरूरत-उन्मुख आर्थिक प्रणाली बनाने के राजनीतिक विचार के रूप में किया जाता है।

93.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी ज़िलों में 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया।
  - यह अभियान कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता के लिये शुरू किया गया था, जो लक्षणहीन (Asymptomatic) हैं या जिनमें हल्के लक्षण हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - इनमें से अधिकांश ज़िले झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में हैं।

- यह अभियान एक विशेष पहल आकांक्षी ज़िला सहयोगी (Aspirational Districts Collaborative) का हिस्सा है जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme-ADP) के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करते हैं।
- इसे जनवरी 2018 में 'आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन' कार्यक्रम (Transformation of Aspirational District' Programme- TADP) के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - आकांक्षी ज़िले भारत के वे ज़िले हैं जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
  - इन ज़िलों में सुधार से भारत के मानव विकास में समग्र सुधार हो सकता है।
- भारत सरकार के स्तर पर यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित है। इसके अलावा अलग-अलग मंत्रालयों ने ज़िलों की प्रगति की जिम्मेदारी संभाली है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

94.

उत्तर : C

व्याख्या :

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिये एक मेंटरशिप प्रोग्राम 'यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स' (YUVA) की घोषणा की है।
  - इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है, जो विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट इंडिया और इसकी संस्कृति और साहित्य को व्यक्त करने के लिये तैयार हों। अत: कथन 1 सही है।
  - मेंटरशिप योजना के तहत छह महीने की अवधि हेतु प्रति लेखक 50,000 रुपए प्रति माह की एक समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (शिक्षा मंत्रालय के अधीन) योजना का चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। अत: कथन 2 सही है।

95.

उत्तर: B

व्याख्या:

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- बजट 2021-22 में सतत् विकास लक्ष्य- 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता)) के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी। अत: कथन 2 सही है।
- जल जीवन मिशन:
  - यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में पाइप से पानी की पहुँच सुनिश्चित करना है।

96.

उत्तर: C

व्याख्या:

- केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु क्षमता विकास के लिये नियम आधारित प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु 'सिविल सेवा क्षमता विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी' को मंज़ूरी दी है। अत: कथन 1 सही है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं के लिये नागरिक अनुभव को बढ़ाना और सक्षम कार्यबल की उपलब्धता में सुधार करना है।
- इस सक्षमता संचालित मिशन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) अर्थात् 'कर्मयोगी भारत' को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- क्षमता निर्माण प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार की गई सामग्री होगी।
- लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के लिये वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक (5 वर्षों की अवधि के दौरान) 510.86 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अत: कथन 3 सही है।

97.

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। अत: कथन 1 सही है।
- इस योजना के तहत होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में तथा अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले 100% केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाता है।

- योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता:
  - व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन: अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र परियोजना लागत के 35% पर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - SHG को प्रारंभिक पूंजी: कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिये प्रति स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG) सदस्य को 40,000 रुपए का प्रारंभिक वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

98.

उत्तर: D

व्याख्या:

- 'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली' (SAFAR) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science) द्वारा महानगरों के किसी स्थान-विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिये शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। अत: कथन 1 सही नहीं हैं।
- यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है, जिसका संचालन भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) द्वारा किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं हैं।
- इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य आम जनता के बीच अपने शहर में वायु गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उचित शमन उपाय और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।
  - सफर, दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता आरंभिक चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) का एक अभिन्न अंग है।
- यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे- तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है।
- इसके अंतर्गत निगरानी किये जाने वाले प्रदूषक हैं: पीएम2.5, पीएम10, ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), बेंज़ीन, टोल्यूनि, ज़ाइलीन और मरकरी। अत: कथन 3 सही नहीं है।

99.

उत्तर: A

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल, 2015 में गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। अत: कथन 1 सही है
  - मुद्रा (MUDRA) यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd) सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। अत: कथन 2 सही है।
  - इसके तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFI) जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नॉन-कॉर्पोरेट स्माल बिज़नस सेक्टर (Non-Corporate Small Business Sector) को वित्तपोषित किया जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं- 'शिशु' (Shishu) 'किशोर' (Kishore) तथा 'तरुण' (Tarun) और ये ऋण लेने वालों के विकास तथा धन संबंधी आवश्यकताओं के चरण को दर्शाते हैं:
  - शिशु: 50,000 रुपए तक के ऋण।
  - किशोर: 50,000 रुपए से 5 लाख लाख रुपए तक के ऋण।
  - तरुण: 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण।
  - इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral-Free Loans) होता है।

100.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्वामित्व (SVAMITVA) का पूर्ण रूप "Survey of Villages And Mapping with Improvised Technology In Village Areas" है।
- हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है।

- स्वामित्व योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरूआत 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) इस योजना का एक नोडल मंत्रालय है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।.

- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (Integrated Property validation Solution) प्रदान करना है।
  - ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और सतत् परिचालन संदर्भ स्टेशन-कॉर्स (Continuously Operating Reference Stations- CORS) नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेमी तक की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-2025 के दौरान संपूर्ण देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा।

101.

उत्तर: (D)

व्याख्या

- हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है।
- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
  - इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। अत: कथन 1 सही है।
- प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
  - हालाँकि अप्रैल 2021 में, सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को फिर से शुरू कर दिया था।
- इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत: कथन 2 सही है।

102.

उत्तर: A

व्याख्या:

- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLAD) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
  - प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के अंतर्गत किया गया जिसे अक्तूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) को स्थानांतरित कर दिया गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों (Member of Parliament) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो किश्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। यह राशि नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है।
- उद्देश्य:
  - इस योजना का उद्देश्य सांसदों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर ज़ोर देना है।
    - इस योजना के अंतर्गत लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर काम करने की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य राज्य के भीतर कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं।
    - राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
    - इन परियोजनाओं में पीने के पानी की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना शामिल है।
  - जून 2016 से इस निधि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan), सुगम्य भारत अभियान (Sugamya Bharat Abhiyan), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Aadarsh Gram Yojana) आदि के कार्यान्वयन में भी किया जाता है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोविड -19 के प्रकोप के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनज़र वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान इस निधि के अस्थायी निलंबन को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

103.

उत्तर: B

व्याख्या:

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH) फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बाँस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ने वर्ष 2021-22 के लिये 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' हेतु 2250 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है। अत: कथन 1 सही है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
  - भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- इसे हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (Green Revolution - Krishonnati Yojana) के तहत लागू किया गया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इसे राज्य बागवानी मिशन (State Horticulture Mission) द्वारा 18 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित ज़िलों में लागू किया जा रहा है।

104.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है।
- इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए की राशि सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
  - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह योजना, भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। अत: कथन 2 सही है।
  - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने का समग्र दायित्त्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को दिया गया है। अत: कथन 3 सही है।

105.

उत्तर: C

व्याख्या:

- अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (ICOM) एक सदस्यता संघ और एक गैर-सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिये पेशेवर एवं नैतिक मानक स्थापित करता है। संग्रहालय क्षेत्र में यह एकमात्र वैश्विक संगठन है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।
  - यह संग्रहालय पेशेवरों (138 से अधिक देशों में 40,000 से अधिक सदस्य) के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
  - ICOM की रेड लिस्ट (खतरे में रहने वाले सांस्कृतिक वस्तुओं से संबंधी), सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिये व्यावहारिक उपकरण है।
    - रेड लिस्ट सांस्कृतिक वस्तुओं की उन श्रेणियों को प्रस्तुत करती है जिनके चोरी होने या किसी अन्य खतरे का डर रहता है।
- विभिन्न संग्रहालयों का प्रभार अलग-अलग मंत्रालयों के पास है अर्थात् सभी संग्रहालय केवल संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं हैं।
  - कुछ संग्रहालयों को ट्रस्टी बोर्ड के तहत मुट्ठी भर लोगों द्वारा सरकारी समर्थन के बिना प्रशासित किया जाता है।
  - नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) का अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का प्रावधान है। अत: कथन 2 सही है।
- संस्कृति मंत्रालय नए संग्रहालयों की स्थापना के लिये सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत राज्य सरकारों और समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों तथा ट्रस्टों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - भारतीय संग्रहालयों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी (संस्कृति मंत्रालय के तहत) को संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण के लिये शुरू किया गया है। अत: कथन 3 सही है।

106.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में विद्युत मंत्रालय (The Ministry of Power) ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में भी योगदान देगा।
- यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा।
- इस मिशन का लक्ष्य खेतों में पराली जलाने (stubble burning) से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना। अत: कथन 2 सही है।
- यह ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

107.

उत्तर: C

व्याख्या:

- 'मिड-डे-मील' योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- इसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल मंत्रालय 'शिक्षा मंत्रालय' है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

108.

उत्तर: A

व्याख्या:

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों पर उनके क्रेडिट की 20% सीमा तक पूर्णत: गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (National Credit Guarantee Trustee Company- NCGTC) द्वारा ECLGS योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 28 मार्च, 2014 को 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। इस कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करना है।
- हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) अवधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसके दायरे को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। अत: कथन 3 सही है।
  - यह सुविधा केवल उन उद्यमों हेतु है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और विलंबित ऋण, यदि कोई हो तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम हो।

109.

उत्तर: D

व्याख्या:

- पीएम-कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था अत: कथन 1 सही नहीं है।
- फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की।
- पीएम-कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी।
- पीएम-कुसुम योजना के घटक:
  - पीएम-कुसुम योजना के तीन घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - घटक A : भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
  - घटक B : 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
  - घटक C : ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)। अत: कथन 2 सही नहीं है।

110.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- 945 करोड़ रूपए लागत की इस योजना को 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) द्वारा लॉन्च किया गया है। अत: कथन 2 सही है।
- पात्रता हेतु आवश्यक शर्तें:
  - DPIIT द्वारा केवल उसी स्टार्टअप, को मान्यता प्रदान की जाएगी जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो।
  - स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त न की जा रही हो। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अगले 4 वर्षों में 300 इन्क्यूबेटर्स (Incubators) के माध्यम से लगभग 3,600 उद्यमियों का समर्थन किया जाएगा।
- DPIIT द्वारा गठित एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Experts Advisory Committee- EAC) योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी हेतु ज़िम्मेदार होगी।

111.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (NBHM) की घोषणा 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के हिस्से के रूप में की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। अत: कथन 1 सही है।
- 'राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड' (NBB) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (NBHM) का उद्देश्य 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और उसका विकसित सुनिश्चित करना है। अत: कथन 2 सही है।
  - लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) ने वर्ष 2000 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत NBB को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया था और जून 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया था।

112.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में चांडलर 'गुड गवर्नेंस इंडेक्स' (CGGI) में भारत को 49वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
  - इस सूची में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- CGGI को चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया है। यह एक निजी गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह सूचकांक 104 देशों के सरकारी क्षमताओं और परिणामों को वर्गीकृत करता है।
- देश में शासन की स्थिति प्रभावों का आकलन करने के लिये 'कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय' (The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) द्वारा भारतीय सुशासन सूचकांक (Good Governance Index- GGI) की शुरुआत की गई है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - जिसके द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

113.

उत्तर: D

व्याख्या:

- SVAMITVA का पूर्ण रूप "Survey of Villages And Mapping with Improvised Technology In Village Areas" है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरूआत 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को 'अधिकार अभिलेख' (Record of Rights) उपलब्ध कराना और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - योजना के पायलट चरण (2020-21) में 6 प्रमुख राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक) के लगभग 1 लाख गाँवों और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँवों को कवर किया जाएगा।
- प्रॉपर्टी कार्ड के लिये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम दिये गए हैं। उदाहरण के लिये हरियाणा में 'टाइटल डीड' (Title Deed), 'कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स'

(Rural Property Ownership Records-RPOR), मध्य प्रदेश में 'अधिकार अभिलेख' (Adhikar Abhilekh), महाराष्ट्र में 'सनद' (Sannad), उत्तराखंड में 'स्वामित्व अभिलेख' (Svamitva Abhilekh) तथा उत्तर प्रदेश में 'घरौनी' (Gharauni)। अत: कथन 2 सही नहीं है।

114.

उत्तर: B

व्याख्या:

- वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1 अप्रैल, 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना।
  - पूर्ण अनुदान सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना।
  - इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- लाभार्थियों का चयन : तीन चरणों के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा जिसमें 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), ग्राम सभा एवं जियो टैगिंग शामिल है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इस योजना की कुल लागत का बँटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

115.

उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इस कार्यक्रम को पहली बार 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2016 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के "कोर ऑफ कोर" (Core of Core) योजनाओं के अंतर्गत लाया गया था। अत: कथन 3 सही है।
- इस योजना के वर्तमान में पाँच घटक हैं:
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
  - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
  - अन्नपूर्णा योजना।
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसे बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।

116.

उत्तर: B

व्याख्या:

- मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है (पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय), यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है।
- यह I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह साल से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करने का प्रावधान करती है। अत: कथन 2 सही है।

117.

उत्तर: (D)

व्याख्या

- यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास हेतु शुरू किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - वर्तमान में 15 थीम आधारित सर्किट हैं - बौद्ध, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्यावरण, विरासत, हिमालयन क्षेत्र, कृष्ण, उत्तर-पूर्व, रामायण, ग्रामीण क्षेत्र, आध्यात्म, सूफी, तीर्थंकर, आदिवासी और वन्यजीव।
  - थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास पर्यटक अनुभव में वृद्धि करने, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने हेतु उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतिस्पर्द्धा और स्थिरता के एकीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।

- पर्यटन मंत्रालय इस योजना के तहत सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिये राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

118.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सरकार ने कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोज़गार के अधिक अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क- मित्रा (Mega Investment Textiles Parks- MI-TRA) योजना प्रस्तावित की है।
- यह योजना निर्यात में भारत को विश्व चैम्पियन बनाने के लिये प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करेगी।
- मित्रा योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive- PLI) के अतिरिक्त आरंभ की जाएगी। अत: विकल्प (A) सही है।

119.

उत्तर: B

व्याख्या:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (जो सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करता है) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है। अत: कथन 1 सही है।
- उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिये जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अत: कथन 2 सही है।
- परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषण तीन चरणों (20:40:40) में किया जाएगा। योजना कार्यान्वयन के परिणामों के आधार पर ही तीसरी किस्त जारी की जाएगी।

120.

उत्तर: D

व्याख्या:

गोबर-धन योजना

- गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इस योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में गाँवों को स्वच्छ बनाने के लिये दो मुख्य घटक शामिल हैं - खुले में शौच मुक्त (ODF) गाँव बनाना और गाँवों में ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन करना।
- इस योजना का उद्देश्य गाँवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण घरों की आय बढ़ाना और मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करना है।
  - इसके अलावा ग्राम स्तर पर आजीविका के नए अवसरों का सृजन और किसानों तथा अन्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है।

121.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये एक 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की है। अत: कथन 1 सही है।
  - मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 'किरण हेल्पलाइन' पर कॉल करने वालों में 70% पुरुष थे, जिनमें अधिकांश युवा थे।
  - शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनो-सामाजिक सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिये 'मनोदर्पण' पहल शुरू की थी। अत: कथन 2 सही नहीं है।

122.

उत्तर: B

व्याख्या:

- मिशन इन्द्रधनुष के तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसके तहत 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ (Vaccine-Preventable Diseases- VPD) के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली खाँसी (Whooping Cough), टेटनस (Tetanus), पोलियो (Polio), क्षय (Tuberculosis), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B), मैनिन्जाइटिस (Meningitis), निमोनिया (Pneumonia), हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B

Infections), जापानी एनसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis), रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine), न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) और खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।

- जापानी एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा ज़िलों में किया जा रहा है। अत: कथन 3 सही है।

123.

उत्तर. A

व्याख्या:

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने और स्वस्थ भारत के लिये एक चार-स्तरीय रणनीति को अपनाने की आवश्यकता के बारे में बात की, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू करना शामिल है।
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों (अंतिम मील तक) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

124.

उत्तर: (B)

व्याख्या

- SATHI (परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान)
  - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अत: युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।
  - उद्देश्य: इसका उद्देश्य शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक ही छत के नीचे उच्च दक्षता से युक्त तकनीकी सुविधाएँ मुहैया कराना है। जिससे शिक्षा, स्टार्ट-अप, विनिर्माण, उद्योग और R&D लैब आदि की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें।
- SATH (सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल) कार्यक्रम:
  - यह NITI Aayog का एक कार्यक्रम है।
  - उद्देश्य: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में परिवर्तन आरंभ करना तथा भविष्य के 'रोल मॉडल' राज्यों का निर्माण करना। अत: युग्म 2 सही सुमेलित है।
- SAATHEE (ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य को लेकर राज्यवार कदम और प्रगति) पोर्टल:
  - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल को विकसित किया गया है जिसका पूरा नाम 'ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य को लेकर राज्यवार कदम और प्रगति'- साथी (State-wise Actions on Annual Targets and Headways on Energy Efficiency-SAATHEE) है। अत: युग्म 3 सही सुमेलित है।

125.

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj), राज्यों के पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department), राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) का सहयोगात्मक प्रयास है।
- उद्देश्य: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना।
  - यह ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन व मानचित्रण की एक योजना है। अत: विकल्प D सही है।
  - मानचित्रण का कार्य पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चार साल की अवधि में वर्ष 2020 से 2024 तक किया जाएगा।

126.

उत्तर: B

व्याख्या:

'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA)

- सरकार ने 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।
- यह अक्तूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- केंद्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100%) मानदंड और परिणाम आधारित है।

- इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण की राशि विशिष्ट संस्थानों तक पहुँचने से पूर्व राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से 'राज्य उच्च शिक्षा परिषदों' को प्रदान की जाती है।
  - विभिन्न राज्यों को वित्तपोषण 'राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं' के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुँच एवं उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा।

नए चरण में परिकल्पना:

- 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों, दूरदराज़/ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर), आकांक्षी ज़िलों, द्वितीय श्रेणी (टियर-2) के शहरों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों आदि तक पहुँच स्थापित करना और सतत् विकास लक्ष्यों का लाभ प्रदान करना है।
- इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके।
- इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिये भी सहयोग दिया जाएगा।
- बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिये राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी।
- भारतीय भाषाओं में सिखाने-सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिये मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा। अत: कथन 2 सही है।

127.

उत्तर: A

व्याख्या:

राष्ट्रीय वयोश्री योजना:

- परिचय:
  - इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस फंड को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। अत: कथन 1 सही है एवं कथन 2 सही नहीं है।
    - छोटे बचत खातों, पीपीएफ और ईपीएफ से सभी दावा रहित राशियों को इस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना है जो क्षीण दृष्टि, श्रवण दोष, दाँतों की क्षति और चलने में व्यवधान आदि उम्र से संबंधित अक्षमता/असमर्थता से पीड़ित हैं। अत: कथन 3 सही है
    - पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण, जैसे- चलने के लिये प्रयोग की जाने वाली छड़ी, कोहनी की बैसाखी, वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा प्रदान किये जाते हैं।
    - वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। वरिष्ठ नागरिकों की 70% से अधिक आबादी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा एक बड़ा प्रतिशत (5.2%) वृद्धावस्था से संबंधित अक्षमता से ग्रसित है।